AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

नई शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा

डॉ. तनुजा गुप्ता, शिक्षा विभाग
माँ विंध्यवासिनी कॉलेज ऑफ एजुकेशन हजारीबाग, झारखंड, भारत

शोध सार

शिक्षा में, एक पाठयक्रम को व्यापक रूप से शैक्षिक प्रक्रिया में होने वाले छात्र अनुभवो की समग्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है। शब्द अक्सर विशेष रूप से निर्देश के नियोजित अनुक्रम को संदर्भित करता है, या शिक्षक या स्कूल के निर्देशात्मक लक्ष्यों के संदर्भ में छात्र के अनुभवों को देखने के लिए। अध्यापन, आमतौर पर शिक्षण के दृष्टिकोण के रूप में समझा जाता है, सीखने के सिद्धांत और अभ्यास को संदर्भित करता है, और यह प्रक्रिया कैसे प्रभाव डालती है, और शिक्षार्थी के सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक विकास से प्रभावित होती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक भारतीय केंद्रित शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके हमारे देश को एक समान और जीवंत ज्ञान वाले समाज में स्थायी रूप से बदलने में सीधे योगदान देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल सिद्धांत तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए रचनात्मकता और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा देकर प्रत्येक छात्र की अद्वितीय क्षमताओं की पहचान करना ओर उन्हें बढ़ावा देना हैं। यह शिक्षण ओर सीखने, भाषा बाधाओं को दूर करने और शैक्षिक योजना ओर प्रबंधन में प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग की सुविधा भी प्रदान करता है। यह स्वायत्तता, सुशासन और सशक्तिकरण के माध्यम से नवाचार और लोक से हटकर विचारों को प्रोत्साहित करता है। यह उत्कृष्ट शिक्षा औ परिनियोजन के लिए अपेक्षित के रूप में उत्कृष्ट अनुसंधान को बढ़ावा देता हैं। उच्च शिक्षा मानव के साथ–साथ सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने और भारत को विकसित करने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसा कि इसके संविधान में कल्पना की गई है – एक लोकतांत्रिक न्यायपूर्ण, सामाजिक रूप से जागरूक, सुसंस्कृत ओर मानवीय राष्ट्र जो सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय को बनाए रखता है। उच्च शिक्षा का उद्देश्य अच्छे, विचारशील, पूर्ण विकसित और रचनात्मक व्यक्तियों का विकास करना होना चाहिए। 21वीं सदी के शिक्षण उपकरण प्रदान करके छात्रों को अकादमिक रूप से सशक्त बनाना।

मुख्य शब्द

उच्च शिक्षा, गुणवतापूर्ण विश्वविद्यालय और कॉलेज, संस्थागत पुनर्गठन, समग्र और बहु–विषयक शिक्षा, समानता और समावेश.

परिचय

नई शिक्षा नीति 2020

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई, 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। नीति पर आधारित मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए समिति ने 15 दिसंबर 2018 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्तुत किया।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री (IB) प्रकाश जावड़ेकर और मानव संसाधन विकास (HRD) और रमेश पोखरियाल निशंक ने NEP-2020 पर घोषणा की। NEP-2020 का उद्देश्य ''भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति'' बनाना है।

चार भाग वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा (भाग I) य उच्च शिक्षा (भाग II) फोकस के अन्य प्रमुख क्षेत्र (भाग III) जैसे कि प्रौढ़ शिक्षा, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना और ऑनलाइन शिक्षा और मेकिंग इट हैपन (भाग IV), जिसमें नीति के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई है।

नई शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांत

मौलिक सिद्धांत जो बड़े पैमाने पर शिक्षा प्रणाली और साथ ही इसके भीतर व्यक्तिगत संस्थानों दोनों का मार्गदर्शन करेंगेः

- शैक्षिणक और गैर–शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक छात्र के समय विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के साथ–साथ माता–पिता को संवेदनशील बनाकर प्रत्येक छात्र की अनूठी क्षमताओं को पहचानना, और बढ़ावा देनाः
- ग्रेड 3 के सभी छात्रों को मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने की सर्वोच्च प्राथमिकता देना।
- लचीलापन होना ताकि शिक्षाथियों में अपने सीखने में सक्षम और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो, और इस तरह वे अपनी प्रतिभा और रूचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सके।
- कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यचर्या और पाठयेतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं आदि के बीच कोई कठिन अलगाव नहीं, ताकि सीखने के विभिन्न क्षेत्रों के बीच हानिकारक पदानुक्रम और प्रणाली को खत्म किया जा सके।
- समग्र शिक्षा के रूप में एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बहु–विषयक, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल को शामिल किया जाय।
- रट्टा मारने और परीक्षा के लिए सीखने के बजाय वैचारिक समझ पर जोर दिया जाय।
- तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए रचनात्मकता और महत्वपूर्ण सोच पर जोर दिया जाय।
- नैतिकता और मानवीय और संवैधानिक मूल्य जैसे सहानुभूति, दुसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सार्वजनिक संपति के लिए सम्मान, वैज्ञानिक स्वभाव, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलवाद, समानता और न्याय पर जोर दिया जाय।
- शिक्षण और सीखने में बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति को बढ़ावा देना, जीवन कौशल जैसे संचार, सहयोग, टीम वर्क और लचीलापन आदि को शामिल किया जाय।
- आज की कोचिंग संस्कृति को प्रोत्साहित करने वाले योगात्मक मूल्यांकन के बजाय सीखने के लिए नियमित रचनात्मक मूल्यांकन पर ध्यान दें।
- शिक्षण और सीखने में प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग भाषा बाधाओं को दूर करना, दिव्यांग छात्रों के लिए पहुँच बढ़ाना और शैक्षिक योजना और प्रबंधन पर ज्यादा विकास किया जाय।
- सभी पाठयक्रम, शिक्षाशास्त्र और नीति में विविधता और स्थानीय संदर्भ के लिए सम्मान, हमेशा यह ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा एक समवर्ती विषय है, इस पर जोर दिया जाय।
- यह सुनिश्चित करने के लिए सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप मे सम्मिलित होने और समावेशन होने में प्रेरित करे ताकि छात्र शिक्षा प्रणाली में फलने–फूलने में सक्ष्म हो।
- बचपन की देखभाल और शिक्षा से लेकर स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठयक्रम में तालमेल होनी चाहिए।
- सीखने की प्रक्रिया के केंद्र के रूप में शिक्षक और संकाय–उनकी भर्ती निरंतर व्यावसायिक विकास, सकारात्मक कार्य वातावरण और सेवा शर्ते को लागू करे।

- स्वायतता, सुशासन और सशक्तिकरण के माध्यम से नवाचार और लीक से हटकर विचारो को प्रोत्साहित करते हुए ऑडिट और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से शैक्षिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन दक्षता सुनिश्चित करने के लिए हल्का लेकिन चुस्त, नियामक ढांचा तैयार हो।
- उत्कृष्ट शिक्षा और विकास के लिए एक उत्कृष्ट शोध के रूप में उत्कृष्ट शोध पर ज्यादा ध्यान देनी चाहिए।
- निरंतर अनुसंधान और शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति की निरंतर समीक्षा की जानी चाहिए।

शिक्षा नीति 2020 का अवलोकन

1. यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय लोकाचार में निहित एक शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है, जो सभी को उच्च गुणवता वाली शिक्षा प्रदान करके भारत, यानी भारत को स्थायी रूप से एक समान और जीवंत ज्ञान समाज में बदलने में योगदान देती है, और इस तरह भारत को वैश्रिक ज्ञान महाशक्ति बनाती है।
2. नीति की परिकल्पना है कि हमारे संस्थानों के पाठयक्रम और शिक्षाशास्त्र को छात्रों के बीच मौलिक कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की गहरी भावना, अपने देश के साथ संबंध और बदलती दुनिया में अपनी भूमिकओं और जिम्मेदारियों के प्रति सचेत जागरूकता विकसित करनी चाहिए।
3. नीति की दृष्टि शिक्षार्थियों में न केवल विचार में बल्कि आत्मा बुद्धि और कर्मा में भारतीय होने के सथ–साथ ज्ञान, कौशल, मूल्यों और स्वभाव को विकसित करने के लिए एक गहरी जड़ें जमाने का है। मानवधिकारों, सतत विकास और रहन–सहन और वैश्विक कल्याण के लिए जिम्मेदार प्रतिबद्धता जिससे वास्तव में वैश्विक नागरिक का पता चलता है।

नई शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा का महत्व

उच्च शिक्षा मानव के साथ–साथ सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने और भारत को विकसित करने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसा कि इसके संविधान में कल्पना की गई है–एक लोकतांत्रिक, न्यायपूर्ण, सामाजिक रूप से जागरूक, सुसंस्कृत और मानवीय राष्ट्र जो सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय को बनाए रखता है। उच्च शिक्षा राष्ट्र के सतत् आजीविका और देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसा कि भारत एक ज्ञान, अर्थव्यवस्था और समाज बनने की ओर बढ़ रहा है, अधिक से अधिक युवा भारतीयों के उच्च शिक्षा के लिए इच्छुक होने की संभावना है।

21वीं सदी की आवश्यकताओं को देखते हुए गुणवतापूर्ण उच्च शिक्षा का उद्देश्य, विचारशील, सर्वागीण और रचनात्मक व्यक्तियों को विकसित करना होना चाहिए। इसे किसी व्यक्ति को गहन स्तर पर रूचि के एक या एक से अधिक विशिष्ट क्षेत्रों का अध्ययन करने में सक्षम बनाना चाहिए, और चरित्रीय नैतिक और संवैधानिक मूल्यों, बौद्धिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक स्वभाव, रचनात्मकता सेवा की भावना और 21वीं सदी की क्षमताओं को कई विषयों में विकसित करना चाहिए। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, भाषाओं के साथ–साथ पेशेवर, तकनीकी और व्यावसायिक विषयों सहित सभी को विकासित करना चाहिए।

एक गुणवतापूर्ण उच्च शिक्षा को व्यक्तिगत उपलब्धि और ज्ञान, रचनात्मक सार्वजनिक जुडाव और समाज में उत्पादक योगदान को सक्षम बनाना चाहिए। इसे छात्रों को अधिक सार्थक और संतोषजनक जीवन और कार्य भूमिकाओं के लिए तैयार करना चाहिए और आर्थिक स्वतंत्रता को सक्षम बनाना चाहिए।

समग्र व्यक्तियों के विकास के उद्देश्य से, यह आवश्यक है कि प्री–स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक सीखने के प्रत्येक चरण में कौशल और मूल्यों का एक निर्धारित मानक शामिल किया जाएगा।

सामाजिक स्तर पर, उच्च शिक्षा को एक प्रबुद्ध सामाजिक रूप से जागरूक, जानकार और कुशल राष्ट्र के विकास को सक्षम बनाना चाहिए जो अपनी समस्याओं का मजबूत समाधान खोज सके, और लागू कर सके। उच्च

शिक्षा को ज्ञान निर्माण और नवाचार का आधार बनाना चाहिए जिससे बढ़ती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान हो।

गुणवतापूर्ण उच्च शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत रोजगार के लिए अधिक अवसर पैदा करने से कहीं अधिक है यह अधिक जीवंत, सामाजिक रूप से व्यस्त, सहकारी समुदायों और एक खुशहाल, एकजुट, सुसंस्कृत, उत्पादक, नवीन, प्रगतिशील और समृद्ध राष्ट्र की कुंजी का प्रतिनिधित्व करता है।

नई शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा के उद्देश्य

उच्च शिक्षा मानव के साथ–साथ सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने और भारत को विकसित करने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसा कि इसके संविधान में कल्पना की गई है–एक लोकतांत्रिक, न्यायपूर्ण, सामाजिक रूप से जागरूक, सुसंस्कृत और मानवीय राष्ट्र जो सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय को बनाए रखता है।

1. उच्च शिक्षा का उद्देश्य अच्छे, विचारशील, पूर्ण विकसित और रचनात्मक व्यक्तियों का विकास करना होना चाहिए। 21वीं सदी के शिक्षण उपकरण प्रदान करके छात्रों को अकादमिक रूप से सशक्त बनाना है।
2. उच्च शिक्षा को एक प्रबृद्ध, सामाजिक रूप से जागरूक, जानकार और कुशल राष्ट्र के विकास को सक्षम बनाना चाहिए जो अपनी समस्याओं का मजबूत समाधान खोजे और लागू कर सके।
3. उच्च शिक्षा अधिक जीवंत, सामाजिक रूप से व्यस्त, सहाकारी समुदायों और एक खुशहाल, एकजुट, सुसंस्कृत, उत्पादक, नवीन, प्रगतिशील और समृद्ध राष्ट्र की कुंजी का प्रतिनिधित्व करती है।
4. उच्च शिक्षा से चारित्रीक, नैतिक और संवैधानिक मूल्यों, बौद्धिक जिज्ञासा सोच, रचनात्मकता, सेवा की भावना और 21वीं सदी की क्षमताओं का विकास होता है।

वर्तमान में भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली के सामने आने वाली कुछ प्रमुख समस्याओं में शामिल हैः

- गंभीर रूप से खंडित उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र।
- संज्ञानात्मक कौशल और सीखने के परिणामों के विकास पर कम जोर।
- अध्ययन के संकीर्ण क्षेत्रों में प्रारंभिक विशेषज्ञता और छात्रों की स्ट्रीमिंग के साथ विषयों का एक कठोर अलगाव।
- विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में सीमित पहुंच कुछ उच्च शिक्षा संस्थान जो स्थानीय भाषाओं में पढ़ाते है।
- सीमित शिक्षक और संस्थागत स्वायत्तता।
- योग्यता आधारित कैरियर प्रबंधन और कॉलेजों में अनुसंधान पर कम जोर, और सभी विषयों में प्रतिस्पर्धी समकक्षों द्वारा प्रसारित शोध फंडिंग की कमी।
- एक अप्रभावी नियामक प्रणाली।
- बडे संबद्ध विश्वविद्यालयों के परिणामस्वरूप स्नातक शिक्षा के निम्र स्तर का होना।

जबकि प्रारंभिक शिक्षा बचपन से बाल्यवस्था तक समग्र बाल विकास का स्तंभ है, उच्च शिक्षा प्रणाली एक छात्र को पेशेवर जीवन के लिए तैयार करती है। रोजगार के लिए रचनात्मक, बहु–विषयक और अत्यधिक कुशल कार्यबल की बढ़ती आवश्यकता के साथ उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली को फिर से समायोजित और नया रूप देने की आवश्यकता है। भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में NEP 2020 में कुछ प्रमुख सुधारों में शामिल हैः

1. गुणवतापूर्ण विश्वविद्यालयों और कॉलेजों

उन समस्याओं को पहचानना जो वर्तमान में भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली में व्याप्त है, जिसमें अन्य बातों

के साथ–साथ शिक्षित कार्यबल की खराब रोजगार क्षमता, गंभीर रूप से खंडित उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र, खराब सीखने के परिणाम और छात्रों के संज्ञानात्मक कौशल का विकास, बहुत विषयों को अलगाव शामिल है। विशेषज्ञता और संकीर्ण क्षेत्रों में छात्रों की स्ट्रीमिंग NEP 2020 भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से सक्रिय करने का इरादा रखता है।

एनईपी 2020 में उच्चशिक्षा प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाने की परिकल्पना की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित बाते शामिल है:

- प्रत्येक जिले में या उसके पास कम से कम एक के साथ बड़े, बहु–विषयक विश्वविद्यालयों ओर कॉलेजों से युक्त एक उच्च शिक्षा प्रणाली की ओर बढ़ना।
- अधिक बहु–विषयक स्नातमक शिक्षा की ओर बढ़ना।
- संकाय और संस्थागत स्वायत्तता की ओर बढ़ना।
- बेहतर छात्र अनुभवों के लिए पाठयक्रम, शिक्षाशास्त्र, मूल्यांकन और छात्र समर्थन को नया रूप देना।
- उत्कृष्ट सहकर्मी–समीक्षा अनुसंधान को वित्त पोषित करने और विश्वविद्यालयों और कॉलेजो में सक्रिय रूप से अनुसंधान के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना करना।
- शैक्षणिक ओर प्रशासनिक स्वायत्तता वाले अत्यधिक योग्य स्वतंत्र बोर्डों द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों का शासन।
- विकलांग शिक्षार्थियों की जरूरतों और वंचित छात्रों के लिए निजी/परोपकारी विश्वविद्यालयों में छात्रवृत्ति में पर्याप्त वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, ओपन स्कूलिंग, ऑनलाइन शिक्षा और ओपन डिस्टेंस लर्निंग सहित कई उपायों के माध्यम से पहुंच, इकिटी और समावेश में वृद्धि करना।

2. संस्थागत पुनर्गठन और समेकन

एनईपी 2020 का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों को बड़े बहुविषय विश्वविद्यालयों और कॉलेजो में बदलकर उच्च शिक्षा के विखंडन को समाप्त करना है, जिनमें से प्रत्येक का लक्ष्य 3000 या अधिक छात्रों को रखना होगा।

NEP 2020 का लक्ष्य यह है कि एक विचार को विद्वानों तथा छात्राओं की एक जीवंत समुदायों का निर्माण करना हैं तथा हानिकारक साइलो को तोड़ना, छात्रों को विषयों (कलात्मक, रचनात्मक और विश्लेषणात्मक विषयो के साथ–साथ खेल सहित) में अच्छी तरह लक्ष्य तक पार करने में सक्षम बनाना है। विषयो (क्रॉस–सहित) में सक्रिय अनुसंधान समुदायों का विकास करना है। अनुशासनात्मक दृष्टिकोण) और उच्च शिक्षा में सामग्री और मानव दोनों के लिए संसाधन दक्षता में वृद्धि करना।

इस प्रकार उच्च शिक्षा प्रणाली में उच्च शिक्षा के बहु–विषयक संस्थानों का प्रस्ताव है जो उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण, अनुसंधान और सामुदायिक जुड़ाव के साथ स्नातक और स्नातक कार्यक्रम प्रदान करते है। सभी उच्च शिक्षा संस्थान अपने संस्थानों में या उच्च शिक्षा संस्थानों के समूहों के माध्यम से पेश किए जाने वाले विषयों और क्षेत्रों में कार्यक्रमों के साथ बडे–बहु–विषयक संस्थान बनने की दिशा में आगे बढ़ेगे।

सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (मौजूदा और साथ ही नए) को गहन अनुसंधान विश्वविद्यालयो, शिक्षण विश्वविद्यालयों और स्वायत डिग्री देने वाले कॉलेजों में विकसित करने की दृष्टि है। शिक्षण और अनुसंधान के अलावा, सभी उच्च शिक्षा संस्थानों की अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारिया भी होगी, जिन्हे वे उपयुक्त संसाधनों और संरचनाओं के माध्यम से निभाएंगे।

3. समग्र शिक्षा को और विकसित करना

एनईपी 2020 छात्रों के सर्वागीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए समग्र कला शिक्षा को बढ़ावा देने की वकालत करता है। इस प्रकार यह प्रस्तावित है कि बहु–विषयक विश्वविद्यालय और कॉलेज पाठयक्रम में लचीलेपन

के साथ उच्च गुणवता वाली कला शिक्षा की ओर बढ़ने की सुवधि प्रदान करेंगे और आकर्षक पाठयक्रम विकल्प विकसित किए जा रहे हैं और छात्रों को पेश किए जा रहे है।

इन पाठयक्रमों के लिए अध्यापन काफी कम रट्टा सीखने और संचार, चर्चा, बहस, अनुसंधान, और अंतः विषय सोच के अवसरो पर अधिक जोर देने का प्रयास करेगा। भाषा, साहित्य,संगीत, दर्शनशास्त्र, भारतविद्या, कला, नृत्य, रंगमंच, शिक्षा गणित, सांख्यिकी, शुद्ध और अनुप्रयुक्त विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, खेल और ऐसे अन्य विषयों में विभाग बहु–विषयक उतेजक भारतीय शिक्षा और पर्यावरण के लिए आवश्यक होंगे। देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानो में स्थापित और मजबूत किया जाएगा।

इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्र अपने सीखने के व्यावहारिक पक्ष से सक्रिय रूप से जुड़े और समग्र शिक्षा के हिस्से के रूप में अपने रोजगार विकल्पों में सुधार करें, छात्रों को स्थानीय उद्योग, व्यवसायों, कलाकारो, शिल्पकारों, गांवो और स्थानीय लोगें के साथ इंटर्नशिप के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। समुदायों, आदि साथ ही संकाय और शोधकर्ताओं के साथ अपने स्वयं के या अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों या अनुसंधान–संस्थानों में अनुसंधान इंटर्नशिप कर पाएंगे।

4. अंतर्राष्ट्रीयकरण

एनईपी 2020 भारत को सस्ती कीमत पर प्रीमियम शिक्षा प्रदान करने वाले वैश्विक अध्ययन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस प्रकार यह इरादा है कि उच्च प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशो में संस्था स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और इसी तरह चुनिंदा विश्वविद्यालयों भारत में संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।

5. शिक्षक की शिक्षा

शिक्षको की एक टीम बनाने के महत्व को पहचानते हुए जो अगली पीढ़ी को आकार देगी। एनईपी 2020 शिक्षक शिक्षा में भी सुधार पर समान रूप से जोर देती है। शिक्षण पेशे की प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए आवश्यक अखंडता और विश्वसनीयता के स्तर तक पहुचने के लिए, नियामक प्रणाली को बुनियादी शैक्षिक मानदंडो को पूरा नहीं करने वाले घटिया और बेकार शिक्षक शिक्षा संस्थानों को चरणबद्ध करने के लिए सशक्त बनाया गया है।

शिक्षक शिक्षा को मनोविज्ञान, दर्शन, समाजशास्त्र, तंत्रिका विज्ञान, भारतीय भाषाओं, कला इतिहास और साहित्य के साथ–साथ विज्ञान, गणित आदि जैसे विभिन्न अन्य विशिष्ट विषयों वाले समग्र बहु आयामी संस्थानों के भीतर संचालित करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, 2030 तक, बहु–विषयक उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रस्तावित 4 वर्षीय एकीकृत बीएड को स्कूल शिक्षको के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता के रूप में बनाने का प्रस्ताव है। उक्त 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड. शिक्षा के साथ–साथ एक विशेष विषय (जैसे भाषा, इतिहास, संगीत, गणित, कंप्यूटर विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, आदि) में एक दोहरी प्रमुख समग्र स्नातक की डिग्री होगी।

शिक्षा के समान स्वीकार्य मानको को बनाए रखने के उद्देश्य से, सेवा–पूर्व शिक्षक कार्यक्रमों में प्रवेश राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित की जाने वाली एकल राष्ट्रव्यापी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा, जिसमें विषय और योग्यता दोनों परीक्षण शामिल हो सकते है।

6. व्यावसायिक शिक्षा

एनईपी 2020 में परिकल्पना की गई है कि व्यावसायिक शिक्षा समग्र उच्च शिक्षा का एक अभिन्न अंग बन जाएगी और इस प्रकार इसमें महत्वपूर्ण और अंतः विषय सोच और अनुसंधान को भी शामिल किया जाना चाहिए।

इस प्रकार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयों कानूनी और कृषि विश्वविद्यालयों या इन क्षेत्रों में संस्थानों को स्थापित करने की प्रथा को हतोत्साहित किया जाएगा और सभी मौजूदा व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों को 2030 तक

बहु–विषयक संस्थान बनना होगा, या तो नए विभाग खोलकर या क्लस्टर में काम करके।

व्यावसायिक शिक्षा मानक जैसे तकनीकी, स्वास्थ्य और कानूनी शिक्षा को भी पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि, शिक्षा के मानक विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी हैं और समय के साथ विकसित होने वाली चुनौतियों के अनुकूल है।

7. उच्च गुणवता वाले अनुसंधान को बढ़ावा देना

एक बड़ी और जीवंत अर्थव्यवस्था को विकसित करने और बनाए रखने और समाज के उत्थान में ज्ञान सृजन और अनुसंधान के महत्व को स्वीकार करते हुए एनईपी 2020 भारत में अनुसंधान की गुणवता और मात्रा को बदलने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण पर केंद्रित है।

इस प्रकार, सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में एक परस्पर संबंधित और समन्वित तरीके से अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने और अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए NEP 2020 एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) की स्थापना का प्रावधान करता है जो अनुसंधान के लिए धन और सहायता में एक बड़ी छलांग लाएगा। NRF का व्यापक लक्ष्य पूरे भारत में विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों के माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना होगा।

इस संबंध में एनआरएफ अन्य बातों के साथ–साथ योग्यता–आधारति सहकर्मी–समीक्षा अनुसंधान निधि का एक विश्वसनीय आधार प्रदान करेगा, जो उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन और मान्यता के माध्यम से देश में अनुसंधान की संस्कृति विकसित करने में मदद करेगा। NRF अकादमिक परिदृश्य में सभी विषयों में प्रतिस्पर्धात्मक रूप से अनुसंधान को निधि देगा। यह निधि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान, कला और मानविकी पर भी दिया जायेगा।

8. उच्च शिक्षा की नियामक प्रणाली को बदलना

वर्तमान में नियामक प्रणाली की यांत्रिक और अशक्त प्रकृति बहुत बुनियादी समस्याओं से व्याप्त है, जैसे कि कुछ निकायों के भीतर शक्ति का भारी संकेंद्रण, इन निकायों के बीच हितों का टकराव और परिणामस्वरूप जवाबदेही की कमी।

इसके अलावा, भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना के लिए दुनिया की कुछ सबसे कठिन आवश्यकताएं भी है, जो भूमि और उसमें मानदंडो, बंदोबस्ती निधियों और उनके स्त्रोतों आदि पर ध्यान केंद्रित करते हुए काफी हद तक उसे कैसे दूर किया जाय इस पर केन्द्रित है।

भारत के भीतर उच्च शिक्षा प्रणाली में वर्तमान में प्रचलित मुद्दों को संबोधित करने के लिए, एनईपी 2020 पूरे शिक्षा क्षेत्र के लिए का सामान्य नियामक व्यवस्था की स्थापना के लिए अनिवार्य है, जिससे नियामक प्रयासों के दोहराव और विघटन को समाप्त किया जा सके। एक एकल नियामक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक प्राधिकरण (एनएचईआरए) की स्थापना 'हल्का लेकिन तंग' और सुविधाजनक तरीके से विनियमित करने के लिए की जाएगी। कुछ महत्व के मामले जैसे, वित्तीय सत्यनिष्ठा, सुशासन और सभी वित, प्रक्रियाओं, संकाय/कर्मचारियों, पाठयक्रमों, शैक्षिक परिणामों के पूर्ण ऑनलाइन और ऑफलाइन सार्वजनिक प्रकटीकारण को बहुत प्रभावी ढंग से विनियमित किया जाएगा।

उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित सीखने के परिणामों को तैयार करने के लिए अलग से एक नई सामान्य शिक्षा परिषद (GEC) की स्थापित की जाएगी, जिसे स्नातक गुण भी कहा जाता है। जीईसी द्वारा एक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता ढांचा (NHEQF) तैयार किया जाएगा और यह राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के अनुरूप होगा।

उच्च शिक्षा अुनदान आयोग (HEGC) बनाया जाएगा जो संस्थानों द्वारा तैयार किए गए IDPs और IDPs

के कार्यान्वयन में हुई प्रगति सहित पारदर्शी मानदंडो के आधार पर उच्च शिक्षा के वित्तपोषण का ध्यान रखेगा।

NEGC नए क्षेत्रों को शुरू करने और सभी विषयों और क्षेत्रों में HEIE में गुणवता कार्यक्रम की पेशकश का विस्तार करने के लिए छात्रवृति और विकासात्मक निधियों के संवितरण का काम सौपा जाएगा।

एनईपी 2020 के संदर्भ में, एक प्रभावी नियामक प्रणाली के मौलिक डिजाइन सिद्धांत इस प्रकार होंगेः

- हितों के टकराव को खत्म करते हुए प्रत्येक आवश्यक भूमिका पर पर्याप्त ध्यान कंद्रित करने के लिए कार्यो का स्पष्ट पृथक्करण करना।
- वित्तीय सत्यनिष्ठा और वित्त प्रक्रियाओं, पाठयक्रम और कार्यक्रम की पेशकश, और शैक्षिक परिणामों के पूर्ण सार्वजनिक प्रकटीकरण जैसी बुनियादी नियामक आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए एक एकल, सशक्त, उतरदायी, लेकिन न्यूनतर नियामक प्राधिकरण, जबकि अन्य संस्थानों को अपने स्वयं के निर्णय लेने के लिए सश्क्त बनाना तथा लक्ष्य तक पहुँचाना है।
- स्वतंत्र बोर्डो द्वारा संचालित नियामक प्रणाली में प्रत्येक निकाय जिसमें प्रासंगिक क्षेत्रों में उच्च विशेषज्ञता के साथ—साथ सत्यनिष्ठा, प्रतिबद्धता और सार्वजनिक सेवा का एक प्रदर्शित रिकॉर्ड शामिल है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब उम्मीद है कि इससे भारत को अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा उठाने में मदद मिलेगी। एनईपी भारत में पूर्व—प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रस्तुत शोधपत्र में राष्ट्रीय नीतियों और शिक्षकों के बीच संबंधी का अध्ययन किया गया था। इसके अलावा, शिक्षक के रूप में शिक्षा की भूमिका पर केंद्रित वर्तमान युवा पीढ़ी के दिमाग को आकार देना है। नए शिक्षा युग में छात्र—शिक्षक संवाद बहुत महत्वपूर्ण है।

संदर्भ सूची

1. बेस्ट जेडब्ल्यू (2006), रिसर्च इन एजुकेशन (9वां संस्करण) नई दिल्लीः प्रेंटिस हॉल इंडिया प्रा. लिमिटेड।
2. मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019।
3. एमएचआरडी.—भारत सरकार (2020) मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई शिक्षा नीति 2020 बुकलेट।
4. एनसीईआरटी (2005) नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005।
5. राधा मोहन (2011) शिक्षा में अनुसंधान के तरीके, नई दिल्लीः नील कमल पब्लिकेशन्स प्रा. लिमिटेड, *एजुकेशनल रिसर्जेस जर्नल,* वॉल्यूम 2, अंक 3, जवनरी 2020 ISBN 2581—9100 42।
6. एसके मंगल (2012) मनोविज्ञान और शिक्षा में सांख्यिकी, दूसरा संस्करण, नई दिल्लीः पीएचआई लर्निग प्राइवेट लिमिटेड।
7. एसजे सखारे (2011, 13 जनवरी) राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत शिक्षण पात्र में रचनावादी दृष्टिकोण का प्रभाव मुंबई।

****